



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 197]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 1987/चैत्र 25, 1909

No. 197]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 1987/CHAITRA 25, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

साथ और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

मा. का. नि. 398(अ).—केंद्रीय सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, शर्तों पर:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) अभिप्रेत है।

(ख) "अभिकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी पक्षकार द्वारा उसकी ओर से राष्ट्रीय आयोग के समक्ष परियाद, अपील या उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया जाए।

(ग) "अपीलार्थी" से ऐसा कोई पक्षकार अभिप्रेत है जो राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील करे।

(घ) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ङ) "ज्ञापन" से अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील का ज्ञापन अभिप्रेत है।

(च) "विरोधी पक्षकार" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो परियाद या दावे का उत्तर देता है;

(छ) "प्रधान" से राष्ट्रीय आयोग का प्रधान अभिप्रेत है;

(ज) "प्रत्यर्थी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपील के किपी ज्ञापन का उत्तर देता है;

(झ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ञ) "राज्य" के अंतर्गत मंत्र राज्य क्षेत्र भी आते हैं;

(ट) उन शर्तों और पदों को जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियम में हैं।

3. केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् और कार्यकारी ग्रुपों का गठन

(1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय परिषद् कहा गया है) गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित 150 सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- (क) नागरिक आपूर्ति विभाग का भार साधक मंत्री जो केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष होगा;
 - (ख) नागरिक आपूर्ति विभाग का राज्य मंत्री (जहां उसका स्वतंत्र भार साधन न हो) या उपमंत्री जो केन्द्रीय परिषद् का उपाध्यक्ष होगा;
 - (ग) राज्यों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री या उपभोक्ता कार्यकलाप के भार साधक मंत्री;
 - (घ) संसद के आठ सदस्य—लोक सभा के पांच और राज्य सभा के तीन;
 - (ङ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त;
 - (च) केन्द्रीय सरकार के ऐसे विभागों और स्वायत्त संगठनों के, जिनका संबंध उपभोक्ता हितों से है, के प्रतिनिधि जिनकी संख्या—बीस से अधिक हो;
 - (छ) उपभोक्ता संगठनों या उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि—पैंतीस से कम नहीं
 - (ज) महिलाओं के प्रतिनिधि—दस से कम नहीं;
 - (झ) किसानों, व्यापार और उद्योगों के प्रतिनिधि—बीस से अधिक;
 - (ञ) ऐसे उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति जिन्हें ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है—पन्द्रह से अधिक;
 - (ट) नागरिक आपूर्ति विभाग का सचिव केन्द्रीय परिषद् का सदस्य-सचिव होगा;
- (2) परिषद् की अवधि तीन वर्ष की होगी।

(3) कोई सदस्य केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा परिषद् से त्यागपत्र दे सकेगा। इस प्रकार या अन्यथा कारित रिकित्या केन्द्र सरकार द्वारा इसी प्रवर्ग से भरी जाएंगी और ऐसा व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह सदस्य, जिसका स्थान उसके द्वारा भरा गया है, पद धारण करने का हकदार होता, यदि पद रिक्त नहीं हुई होती।

4. केन्द्रीय परिषद् की प्रक्रिया :—धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय परिषद् अपने कारबार संचालन की द्वाबत निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगी :—

- (1) केन्द्रीय परिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष केन्द्रीय परिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में केन्द्रीय परिषद्, परिषद् के उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी सदस्य को निर्वाचित करेगी।
- (2) केन्द्रीय परिषद् का अधिवेशन प्रत्येक सदस्य को सूचना जारी करने की तारीख से कम से कम दस दिन की लिखित सूचना देकर बुलाई जाएगी।
- (3) केन्द्रीय परिषद् के अधिवेशन की प्रत्येक सूचना में, अधिवेशन का स्थान, दिन और समय विनिर्दिष्ट होगा तथा उसमें वहां के कारबार संचालन का विवरण अंतरविष्ट होगा।
- (4) केन्द्रीय परिषद् की कोई कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधि-मान्य नहीं होगी कि परिषद् में कोई स्थान रिक्त है या परिषद् के गठन में कोई दोष है।
- (5) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय परिषद् अपने सदस्यों में से ऐसे कार्यकारी ग्रुपों का गठन कर सकेगी जिसे वह आवश्यक समझे और इस प्रकार

गठित प्रत्येक कार्यकारी ग्रुप ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो केन्द्रीय परिषद् द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं। ऐसे कार्यकारी ग्रुपों के निष्कर्षों को केन्द्रीय परिषद् के समक्ष विचार करने के लिए पेज किया जाएगा।

- (6) गैर सरकारी सदस्य केन्द्रीय परिषद् या कार्यकारी ग्रुप के अधिवेशन में भाग लेने के लिए आने जाने के लिए प्रथम श्रेणी रेल भाड़े के, और प्रतिदिन एक सौ रुपये दैनिक भत्ते के हकदार होंगे। संसद सदस्य ऐसी दरों पर, जो ऐसे सदस्यों को अनुज्ञेय है, यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।
- (7) केन्द्रीय परिषद् द्वारा पारित संकल्प सिफारिशी प्रकृति के होंगे।

5. राष्ट्रीय आयोग का स्थान—राष्ट्रीय-आयोग का कार्यालय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित होगा।

6. राष्ट्रीय आयोग के कार्यदिवस और कार्यालय समय—राष्ट्रीय आयोग के कार्यदिवस और कार्यालय समय वही होंगे जो केन्द्रीय सरकार के हैं।

7. मुद्रा और संप्रतीक—राष्ट्रीय आयोग की शासकीय मुद्रा और संप्रतीक ऐसा होगा जैसा केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।

8. राष्ट्रीय आयोग की बैठक—राष्ट्रीय आयोग की बैठक जब कभी आवश्यक हो, प्रधान द्वारा बुलाई जाएगी।

9. राष्ट्रीय आयोग के कर्मचारी—केन्द्रीय सरकार ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति करेगी जो राष्ट्रीय आयोग के दिन-प्रतिदिन कार्य में सहायता करने और अन्य ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो जो अधिनियम और इन नियमों के अधीन उपबंधित किए गए हों या प्रधान द्वारा आयोग को समनुदेशित किए गए हों। ऐसे कर्मचारियों को संदेय बेतन भारत की संचित निधि से अदा की जाएगी।

10. राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला फोरम की अतिरिक्त शक्तियां—(1) राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोग और जिला फोरम को किसी व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा करने की शक्ति होगी—

- (क) यदि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी ऐसी पुष्टि लेखाओं, दस्तावेजों या वस्तुओं की परीक्षा करने अपेक्षित हो तो, यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला फोरम के इस निमित्त, विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी के समक्ष अध्यक्षता में यथाविनिर्दिष्ट या वर्णित पुस्तकों, लेखों, दस्तावेज या वस्तुएं जो इस प्रकार अपेक्षित व्यक्ति की अभिरक्षा में या नियंत्रणाधीन हो, प्रस्तुत करना और उसकी परीक्षा करने देना और रखने देना;

- (ख) इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारी को ऐसी सूचना देना जिसकी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाए।

(2) (क) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला फोरम को ऐसा विश्वास करने का कोई कारण हो कि कोई पुस्ति, कागज, वस्तु या दस्तावेज जिसे ऐसी कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत करने की अपेक्षा हो सकती है, नष्ट, विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकृत किए जा रहे हैं या किए जा सकते हैं या छिपाए जा रहे हैं या छिपाए जा सकते हैं, वहां वह लिखित आदेश द्वारा किसी अधिकारी को किसी परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। ऐसा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी पुस्तक, कागजों, दस्तावेजों या वस्तुओं का जिसकी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपेक्षा हो अभिग्रहण कर सकेगा।

परन्तु ऐसे अभिग्रहण की संसूचना यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला फोरम को ऐसे अभिग्रहण किए जाने के 72 घण्टे से अधिक अवधि के भीतर शीघ्रातिशीघ्र ऐसे अभिग्रहण किए जाने के कारण लिखित रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए, दी जाएगी।

(ख) यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला फोरम ऐसी अभिलेखित दस्तावेजों या वस्तुओं की, यथास्थिति, परीक्षा करने के पश्चात् उनके रखे जाने का आदेश कर सकेगा या उन्हें संबंधित पक्षकार को वापिस कर सकेगा।

11. राष्ट्रीय आयोग के प्रधान और सदस्यों के वेतन, मानदेय और अन्य भत्ते—

(1) जहाँ राष्ट्रीय आयोग का प्रधान उच्चतम न्यायालय का आसीन न्यायाधीश है, वह ऐसे सभी फायदों का उपभोग करेगा जिनका उपभोग वह उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश के रूप में करता, जहाँ प्रधान उच्चतम न्यायालय का आसीन न्यायाधीश नहीं हो, वहाँ वह प्रति मास 8,000 रु. का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य, यदि वे पूर्ण कालिक आधार पर आसीन हैं, प्रतिमास 6,000 रु. का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे या यदि अंशकालिक आधार पर आसीन हैं तो बैठकों के लिए प्रतिदिन 300 रु. का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।

(2) प्रधान और सदस्य सरकारी दौरे पर उन्हीं दौरे पर यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

(3) यथास्थिति मानदेय या वेतन और अन्य भत्ते भारत की संचित निर्धिष्ट से अदा किए जाएंगे।

12. राष्ट्रीय आयोग के प्रधान और सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें—

(1) राष्ट्रीय आयोग के प्रधान और सदस्य को नियुक्ति से पूर्व, यह परिबचन करना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न होगा जिससे ऐसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) प्रधान और सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो पांच वर्ष से अधिक हो जैसा अधिसूचना में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किन्तु वे पुनःनियुक्ति के पात्र होंगे।

परन्तु कोई प्रधान या सदस्य 10 वर्ष से अधिक कुल अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् जो भी पूर्वतर हो, उस हिसाब में पद धारण नहीं करेगा।

(3) उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रधान या सदस्य—

(क) किसी भी समय केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेखे द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) नियम 13 के उपनियमों के अनुसार अपने पद से हटाया जा सकेगा;

(4) प्रधान और सदस्यों की सेवा में निबंधन और शर्तें उनके पद की कालावधि के दौरान उनके लिए अहितकर रूप में परिवर्तित नहीं की जाएगी।

(5) उप-नियम (3) के अधीन या अन्यथा राष्ट्रीय आयोग के प्रधान या किसी अन्य सदस्य के पद त्याग करने या हटाए जाने से धारित कोई आकस्मिक रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी।

(6) जहाँ राष्ट्रीय आयोग के प्रधान के पद पर ऐसी आकस्मिक रिक्ति होती है, तत्समय पद धारण करने वाला राष्ट्रीय आयोग का ज्येष्ठतम (नियुक्ति के क्रम से) सदस्य तब तक प्रधान के कृत्यों का निहित करेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति राष्ट्रीय आयोग के प्रधान का पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(7) जब राष्ट्रीय आयोग का प्रधान अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रीय आयोग

का ज्येष्ठतम (नियुक्ति के क्रम में) सदस्य उस तारीख तक प्रधान के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिसको प्रधान फिर से कार्यभार संभाल लेता है।

(8) राष्ट्रीय आयोग की कोई कार्रवाई या कार्यवाही केवल इन कारणों से अविविमान्य नहीं होगी कि उसके प्रधान या सदस्य का कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई दोष है।

(9) राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी तथा आयोग की राय या आदेश बहुमत के विचार के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे।

(10) प्रधान या कोई सदस्य जिसका इस हिसाब में पद धारण करना समाप्त हो जाता है, किसी ऐसे संगठन के प्रबंध या शासन या उससे संबंधित में, जो उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का विषय रहा हो, उस तारीख से, जिसको उसका ऐसा पद धारण करना समाप्त हो जाता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई नियुक्ति धारण नहीं करेगा।

13. कुछ परिस्थितियों में पद से प्रधान या सदस्यों का हटाया जाना—

(1) केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे प्रधान या सदस्य को पद से हटा सकती जो—

(क) विवालिया अधिनियमित किया जा चुका है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्भूत है; या

(ग) जो शारीरिक या मानसिक रूप से प्रधान या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए असमर्थ हो चुका हो; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अज्ञित कर लिया है जिससे प्रधान या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या

(ङ) जिसने अपनी हिसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बना रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

(2) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रधान या किसी सदस्य को उस उपनियम के खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर उसके पद से हटाया नहीं जाएगा, विवाय केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जांच के द्वारा जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और जिसमें प्रधान या सदस्य इस आधार पर दोषी पाया जाए।

14. राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—

(1) परिवाद, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, परिवादी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके अभिकर्ता द्वारा राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा या राष्ट्रीय आयोग के पते पर रजिस्ट्रार आदिक द्वारा भेज दिया जाएगा :—

(क) परिवादी का नाम, वर्णन और पता;

(ख) यथास्थिति विरोधी पक्षकार या पक्षकारों के नाम, वर्णन और पता जहाँ तक वे अभिनिश्चित किए जा सकें;

(ग) परिवाद से संबंधित तथ्य और वे कब और कहाँ पैदा हुए;

(घ) परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों के समर्थन में दस्तावेज;

(ङ) वह अनुतोष जिसका परिवादी दावा करता हो।

(2) राष्ट्रीय आयोग अपने समक्ष पेश किसी परिवाद के निपटारे में, यथासंभव, किसी जिला फोरम द्वारा प्राप्त किए गए परिवाद से संबंधित धारा 13 की उपधारा (1) और (2) में अधिकृत प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(3) सुनवाई की तारीख को या किसी अन्य तारीख का जिसका सुनवाई स्थिति की जाए, पक्षकारों या उनके अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के समक्ष हाजिर होना बाध्यकारी होगा। अहाँ परिश्रम या उसका अधिकारी ऐसी तारीखों पर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है वहाँ राष्ट्रीय आयोग अपने विवेकानुसार परिवार को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर या गुणावगुण से आधार उसका विनिश्चय कर सकेगा। जहाँ विरोधी पक्षकार या उसका अधिकारी सुनवाई की तारीख को हाजिर होने में असफल रहता है वहाँ राष्ट्रीय आयोग परिवार का एक-पक्षीय रूप से विनिश्चय कर सकेगा।

(4) राष्ट्रीय आयोग, ऐसे निबंधनों पर जिन्हें वह उचित समझता है और कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर, परिवार की सुनवाई स्थिति कर सकेगा किन्तु अहाँ परिवार में वस्तुओं के विनिष्पन्न या परीक्षण की अपेक्षा न हो वहाँ-जहाँ तक संबंध हो सके परिवार का विनिश्चय विरोधी पक्षकार द्वारा सूचना प्राप्त करने की तारीख से तीन मास के भीतर और यदि वस्तुओं के विनिष्पन्न या परीक्षण की अपेक्षा हो तो पांच मास के भीतर किया जाएगा।

(5) यदि उपनियम (3) के अधीन की गई कार्यवाही के पश्चात् राष्ट्रीय आयोग का परिवार में अतिरिक्त अधिकारियों के संबंध में यह समाधान हो जाता है तो वह समाप्ति, विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को धारा 14 की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई एक या अधिक बातें करने का निदेश देते हुए आदेश जारी कर सकेगा। राष्ट्रीय आयोग को यह निदेश देने की भी शक्ति होगी कि इसके द्वारा पारित कोई आदेश, जहाँ धारा 23 के अधीन कोई अपील नहीं की गई है या जहाँ उस धारा के अधीन राष्ट्रीय आयोग के आदेश की उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि कर दी गई है, राजपत्र में या किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित किया जाए। प्रकाशन के लिए राष्ट्रीय आयोग या किसी माध्यम के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

15. अपील की सुनवाई के लिए प्रक्रिया -

(1) आपन अपीलार्थी या उसके अधिकारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा या आयोग के पत्र पर रजिस्ट्री-कृत डाक द्वारा भेज दिया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन फाइल किया गया प्रत्येक आपन युवाद्य हस्तलेख में अधिमानतः टाइप किया हुआ होगा तथा बिना किसी तर्क या वृत्तों के अपील के आधार पर स्पष्ट शीर्षकों के अधीन माध्यम प्ररूप में दिए जाएंगे और ऐसे आधार क्रम से संख्यांकित किए जाएंगे।

(3) प्रत्येक आपन के साथ राज्य आयोग के आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, अभिप्रमाणित प्रति और ऐसे दस्तावेज, जो आपन में उचित आक्षेप के आधार के समर्थन के लिए अधिस्तित हों, होंगे।

(4) जब अपील अधिनियम में विनिर्दिष्ट परिसीमाकाल की समाप्ति के पश्चात् की जाए तो आपन के साथ एक आवेदन होगा जो ऐसे आपन पत्र से सम्बंधित होगा जिसमें ऐसे तथ्य दिए जाएंगे जिनके आधार पर अपीलार्थी राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान करने के लिए विवक्षित हो कि परिसीमाकाल के भीतर अपील न करने का उसके पास पर्याप्त कारण है।

(5) अपीलार्थी शायकीय प्रयोजन के लिए आयोग को आपन की छह प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(6) सुनवाई की तारीख को या किसी अन्य दिवस को जिसका सुनवाई स्थिति की जाए, पक्षकारों या उनके अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के समक्ष हाजिर होना बाध्यकारी होगा। यदि अपीलार्थी या उसका अधिकारी ऐसी तारीख पर हाजिर होते में असफल रहता है तो वह राष्ट्रीय आयोग के स्वविवेकानुसार अपील को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर या गुणावगुण के आधार पर एकपक्षीय विनिश्चय कर सकेगा। यदि प्रत्यर्थी या उसका अधिकारी ऐसी तारीख को हाजिर होने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय आयोग एकपक्षीय कार्यवाही करेगा और मामले के गुणावगुण के आधार पर अपील का विनिश्चय करेगा।

(7) अपीलार्थी, राष्ट्रीय आयोग की इजाजत के बिना आपन में न दिए गए आक्षेप के किसी आधार के समर्थन में न तो किसी बात पर जोर देगा और न ही उस सुना जाएगा - किन्तु राष्ट्रीय आयोग, अपील का विनिश्चय करने समय आपन में दिए गए आक्षेप के आधार तक सीमित नहीं रहेगा।

परन्तु आयोग अपना विनिश्चय आपन में विनिर्दिष्ट आधारों से भिन्न किसी अन्य आधार पर तब तक आधारित नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रीय आयोग उससे प्रभावित हो सकने वाला पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दे देता है।

(8) राष्ट्रीय आयोग ऐसे निबंधनों पर जिन्हें वह उचित समझता है और किसी भी प्रक्रम पर अपील की सुनवाई स्थिति कर सकेगा किन्तु साधारणतः एक स्थान से अधिक नहीं दिया जाएगा और अपील का विनिश्चय यथासंभव सुनवाई की पहली तारीख से नब्बे दिन के भीतर किया जाना चाहिए।

(9) अपील पर राष्ट्रीय आयोग का आदेश राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षरित होगा और पक्षकारों को उसकी निशुल्क प्रतियां दी जाएगी।

[मिगिल सं. 9/11/86 से पी. ग.]

बो. के. मिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 15th April, 1987

NOTIFICATION

GSR 398(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Consumer Protection Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986);

(b) "agent" means a person duly authorised by a party to present any complaint, appeal or reply on its behalf before the National Commission;

(c) "appellant" means a party which makes an appeal against the order of the State Commission;

(d) "chairman" means a chairman of the Central Consumer Protection Council established under sub-section (1) of the section 4 of the Act;

(e) "memorandum" means any memorandum of appeal filed by the appellant;

(f) "opposite party" means a person who answers complaint or claim:

- (g) "president" means the President of the National Commission;
- (h) "respondent" means the person who answers any memorandum of appeal;
- (i) "section" means section of the Act;
- (j) "state" includes Union territories also;
- (k) words and expressions used in the rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The constitution of the Central Consumer Protection Council and the Working Groups—

(1) The Central Government shall, by notification in the official Gazette constitute the Central Consumer Protection Council (hereinafter referred to as the Central Council) which shall consist of the following 150 members namely:—

- (a) the Minister in-charge of Department of Civil Supplies who shall be the Chairman of the Central Council;
- (b) the Minister of State (where he is not holding independent charge) or Deputy Minister in the Department of Civil Supplies who shall be the Vice-Chairman of the Central Council;
- (c) the Ministers of Food and Civil Supplies or Minister in-charge of Consumer Affairs in States;
- (d) eight Members of Parliament—five from the Lok Sabha and three from the Rajya Sabha;
- (e) the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes;
- (f) representatives of the Central Government Departments and autonomous organisations concerned with consumer interests—not exceeding twenty;
- (g) representatives of the Consumer Organisations or consumers—not less than thirty-five;
- (h) representatives of women—not less than ten;
- (i) representatives of farmers, trade and industries—not exceeding twenty;
- (j) persons capable of representing consumer interests not specified above—not exceeding fifteen;
- (k) the Secretary in the Department of Civil Supplies shall be the member secretary of the Central Council.

(2) The term of the Council shall be three years.

(3) Any member may, by writing under his hand to the Chairman of the Central Council, resign from the Council. The vacancies, so caused or otherwise, shall be filled from the same category by the Central Government and such person shall hold office so long

as the member whose place he fills would have been entitled to hold office, if the vacancy had not occurred.

4. Procedure of the Central Council—Under subsection (2) of section 5, the Central Council shall observe the following procedure in regard to the transaction of its business:—

- (1) The meeting of the Central Council shall be presided over by the Chairman. In the absence of the Chairman, the Vice-Chairman shall preside over the meeting of the Central Council. In the absence of the Chairman and the Vice-Chairman, the Central Council shall elect a member to preside over that meeting of the Council.
- (2) Each meeting of the Central Council shall be called by giving not less than ten days from the date of issue, notice in writing to every member.
- (3) Every notice of a meeting of the Central Council shall specify the place and the day and hour of the meeting and shall contain statement of business to be transacted thereat.
- (4) No proceedings of the Central Council shall be invalid merely by reasons of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Council.
- (5) For the purpose of performing its functions under the Act, the Central Council may constitute from amongst its members, such working groups as it may deem necessary and every working group so constituted shall perform such functions as are assigned to it by the Central Council. The findings of such working groups shall be placed before the Central Council for its consideration.
- (6) The non-official members shall be entitled to first class to and fro Railway fare and a daily allowance of one hundred rupees per day for attending the meetings of the Central Council or any working group. Members of Parliament shall be entitled to travelling and daily allowances at such rates as are admissible to such members.
- (7) The resolutions passed by the Central Council shall be recommendatory in nature.

5. Place of the National Commission—The office of the National Commission shall be located in the Union Territory of Delhi.

6. Working days and office hours of the National Commission—The working days and office hours of the National Commission shall be the same as that of the Central Government.

7. Seal and emblem—The official seal and emblem of the National Commission shall be such as the Central Government may specify.

8. Sitzings of the National Commission—The sitting of the National Commission as and when necessary shall be convened by the President.

9. Staff of the National Commission—The Central Government shall appoint such staff as may be necessary to assist the National Commission in its day to day work and to perform such other functions as are provided under the Act and these rules or assigned to it by the President. The salary payable to such staff shall be defrayed out of the Consolidated Fund of India.

10. Additional powers of the National Commission, State Commission and District Forum—(1) The National Commission, the State Commission and the District Forum shall have power to require any person,—

- (a) to produce before, and allow to be examined and kept by an officer of the National Commission, the State Commission or the District Forum, as the case may be, specified in this behalf, such books accounts, documents or commodities in the custody or under the control of the person so required as may be specified or described in the requisition, if the examination of such books accounts, documents or commodities are required for the purpose of this Act;
 - (b) to furnish to an officer so specified, such information as may be required for the purpose of this Act.
- (2) (a) Where during any proceedings under this Act the National Commission, the State Commission or the District Forum as the case may be, has any ground to believe that any book, paper, commodity or document which may be required to be produced in such proceeding are being, or may be destroyed mutilated, altered, falsified or secreted, it may, by written order authorise any officer to exercise the power of entry and search of any premises. Such authorised officer may also seize such books, papers, documents or commodities as are required for the purpose of this Act;

Provided that such seizure shall be communicated to the National Commission, the State Commission or the District Forum, as the case may be, as soon as it is made or within a period not exceeding 72 hours of making such seizure after specifying the reasons in writing for making such seizure.

- (b) The National Commission, the State Commission or the District Forum, as the case may be, on examination of such seized documents or commodities, as the case may be, may order the retention thereof or may return it to the party concerned.

11. Salaries honorarium and other allowances of the President and Members of the National Commission—(1) Where the President of the National Commission is a sitting judge of the Supreme Court, he shall enjoy all the benefits which he should have enjoyed as sitting judge of the Supreme Court. Where the President is not a sitting judge of the Supreme Court, he shall receive a consolidated honorarium of Rs. 8000 per month. Other members, if sitting on

whole-time basis shall receive a consolidated honorarium of Rs. 6,000 per month or if sitting on part-time basis, a consolidated honorarium of Rs. 300 per day for sittings.

(2) The President and the members shall be entitled to travelling and daily allowances on official tours at the same rates as are admissible to Group 'A' Officer of the Central Government.

(3) The honorarium or the salary, as the case may be and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of India.

12. Terms and conditions of service of the President and members of the National Commission.—(1) Before appointment, the President and a member of the National Commission shall have to take an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interests as is likely to effect prejudicially his functions as such member.

(2) The President and the member shall hold office for such period, not exceeding 5 years as may be specified by the Central Government in the notification, but shall be eligible for re-appointment.

Provided that no President or a member shall hold office as such for a total period exceeding 10 years or after he has attained the age of 65-years, whichever is earlier.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) the President or a member may,—

- (a) by writing under his hand and addressed to the Central Government resign his office at any time;
- (b) be removed from his office in accordance with the provisions of rule 13.

(4) The terms and conditions of service of the President and the members shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

(5) A casual vacancy caused by resignation or removal of the President or any other member of the National Commission under sub-rule (3) or otherwise shall be filled by fresh appointment.

(6) Where any such casual vacancy occurs in the office of the President of the National Commission, the senior-most (in order of appointment) member of the National Commission holding office for the time being, shall discharge the functions of the President until a person appointed to fill such vacancy assumes the office of the President of the National Commission.

(7) When the President of the National Commission is unable to discharge the functions owing to absence, illness or any other cause, the senior-most (in order of appointment) member of the National Commission shall discharge the functions of the President until the day on which the President resumes the charge of his function.

(8) No act or proceedings of the National Commission shall be invalid by reasons only of the existence of any vacancy among its President or members or any defect in the constitution thereof.

(9) In case of a difference of opinion among the members of the National Commission, the opinion of the majority shall prevail and the opinion or orders of the Commission shall be expressed in terms of the views of the majority.

(10) The President or any member ceasing to hold office as such shall not hold any appointment in or be connected with the management or administration of any organisation which have been the subject of any proceeding under the Act during his tenure for a period of 5 years from the date on which he ceases to hold such office.

13. Removal of President or members from office in certain circumstances.—(1) The Central Government may remove from office, the President or any member who,—

- (a) has been adjudged an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as the President or the member; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the President or a member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the President or any member shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d) and (e) of that sub-rule except on an inquiry held by Central Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf and finds the President or a member to be guilty of such ground.

14. Procedure to be followed by the National Commission.—(1) A complaint containing the following particulars shall be presented by the complainant in person or by his agent to the National Commission or be sent by registered post addressed to the National Commission:—

- (a) the name, description and the address of the complainant;
- (b) the name, description and address of the opposite party or parties, as the case may be, so far as they can be ascertained;
- (c) the facts relating to complaint and when and where it arose;
- (d) documents in support of the allegations contained in the complaint;
- (e) The relief which complaint claims.

(2) The National Commission shall, in disposal of any complaint before it, as far as possible, follow the procedures laid down in sub-sections (1) and (2) of section 13 in relation to complaint received by the District Forum.

(3) On the date of hearing or any other date to which hearing could be adjourned, it shall be obligatory on the parties or their agents to appear before the National Commission. Where the complainant or his agent fails to appear before the National Commission on such days, the National Commission may in its discretion either dismiss the complaint for default or decide it on merits. Where the opposite party or its agent fails to appear on the date of hearing, the National Commission may decide the complaint ex-parte.

(4) The National Commission may, on such terms as it deems fit and at any stage of the proceedings, adjourn the hearing of complaint but the complaint shall be decided, as far as possible, within a period of three months from the date of notice received by opposite party where complaint does not require analysis or testing of commodities and within five months if it requires analysis or testing of commodities.

(5) If after the proceedings conducted under sub-rule (3) the National Commission is satisfied with the allegations contained in the complaint it shall issue orders to the opposite party or parties, as the case may be, directing him or them to take one or more of the things as mentioned in sub-section (1) of section 14. The National Commission shall also have the power to direct that any order passed by it, where no appeal has been preferred under section 23 or where the order of the National Commission has been affirmed by the Supreme Court under that section, be published in the Official Gazette or through any other media and no legal proceedings shall lie against the National Commission or any media for such publication.

15. Procedure for hearing the appeal.—(1) memorandum shall be presented by the appellant or his agent to the National Commission in person or be sent by registered post addressed to the Commission.

(2) Every memorandum filed under sub-rule (1) shall be in legible handwriting preferably typed and shall set forth concisely under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds shall be numbered consecutively.

(3) Each memorandum shall be accompanied by a certified copy of the order of the State Commission appealed against and such of the documents as may be required to support grounds of objection mentioned in the memorandum.

(4) When the appeal is presented after the expiry of the period of limitation as specified in the Act, the memorandum shall be accompanied by an application supported by an affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the National Commission that he has sufficient cause for not preferring the appeal within the period of limitation.

(5) The appellant shall submit six copies of the memorandum to the Commission for official purpose.

(6) On the date of hearing or on any other day to which hearing may be adjourned, it shall be obligatory for the parties or their agents to appear before the National Commission. If appellant or his agent fails to appear on such date, the National Commission

may in its discretion either dismiss the appeal or decide ex-parte on merits. If the respondent or his agent fails to appear on such date, the National Commission shall proceed ex-parte and shall decide the appeal on merits of the case.

(7) The appellant shall not, except by leave of the National Commission, urge or be heard in support of any ground of objection not set forth in the memorandum but the National Commission, in deciding the appeal, may not confine to the grounds of objection set forth in the memorandum:

Provided that the Commission shall not rest its decision on any other ground other than those specified in the memorandum unless the party who may be affected thereby, has

been given an opportunity of being heard by the National Commission.

(8) The National Commission, on such terms as it may think fit and at any stage, adjourn the hearing of the appeal, but not more than one adjournment shall ordinarily be given and the appeal should be decided, as far as possible within 90 days from the first date of hearing.

(9) The order of the National Commission on appeal shall be signed and dated by the members of the National Commission and shall be communicated to the parties free of charge.

[File No. 9/11/86-CPU]

B. K. SINHA, Jt. Secy.